Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

अक्तूबर 2023 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- उत्तराखंड के धारे-नौले और जलस्रोतों को सँवारेगी सारा 3
- उत्तराखंड में 28 नवंबर से होगा 6वाँ वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 3
- मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का हुआ उद्घाटन 4
- वैश्विक निवेशक सम्मेलन: दिल्ली रोड शो में 19,385 करोड़ रुपए के निवेश पर करार 8
- समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप, स्विटज़रलैंड के मध्य किया गया समझौता ज्ञापन 9
- 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस 10
- उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित 11
- मुख्यमंत्री ने रोज़गार प्रयाग पोर्टल और 'युवा उत्तराखंड एप' को लॉन्च किया 12
- बुलेट रिकवरी बॉक्स 14
- प्रदेश में पहली बार पर्यटक स्थलों का कराया जाएगा सर्वे 15
- उत्तराखंड में होगा एसआईएसएफ और पर्यटन पुलिस का गठन 16
- 'ऐपण महोत्सव' का हुआ शुभारंभ 20
- 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड से 18 खेलों में 140 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग 22
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुमाऊँ यात्रा में बना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड 22
- मुख्यमंत्री ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के कार्यालय का किया शुभारंभ 24
- उत्तराखंड खेल महाकुंभ 2023 25
- उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को फिल्म 'एक था गाँव' के लिये मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 26
- उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वेलनट मिशन शुरू करेगी राज्य सरकार 27
- दुबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 5450 करोड़ रुपए के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन 28
- वीपीकेएएस में 47वाँ कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 30
- बिल लाओ इनाम पाओ योजना: विजेताओं को वित्त मंत्री ने दिये पुरस्कार 30
- देश में कुल उत्पादन का 20 फीसदी दवाएँ बना रहा प्रदेश 32
- राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव तैयार 33
- सौ करोड़ रुपए से बनाए जाएंगे पुलिसकर्मियों के आवास 34
- राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन मालसी (देहरादून) में 35
- उत्तरकाशी ज़िले में की जाएगी काले गेहूँ की खेती 35
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना शामिल 36
- वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 38
- महाविद्यालयों को पाँच से 10 लाख रुपए पुरस्कार देगी सरकार 38
- उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग के बीच बनेगी कंक्रीट की दीवार 39
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉ. गोदियाल 40
- मछली पालन को बढ़ावा देने को शुरू होगी 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना' 42
- उत्तराखंड के सूरज पंवार ने रेस वॉकिंग में जीता गोल्ड मेडल 42
- मुख्यमंत्री ने किया सतर्कता सप्ताह का शुभारंभ 43
- कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी 44

नोट :

उत्तराखंड

उत्तराखंड के धारे-नौले और जलस्रोतों को सँवारेगी सारा

चर्चा में क्यों ?

2 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड शासन के अपर मुख्य सचिव, आनंद वर्द्धन ने बताया कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा में रचे-बसे नौले-धारों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिये एकीकृत एजेंसी बनाने की तैयारी है। इसके लिये शासन स्तर पर स्प्रिंगशेड एंड रिवर रिजुवेनेशन एजेंसी (सारा) के गठन की कवायद की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- अपर मुख्य सचिव, आनंद वर्द्धन ने बताया कि प्रदेश में नौले-धारों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने को लेकर कवायद शुरू की गई है। इसके लिये स्प्रिंगशंड एंड रिवर रिजुविनेशन एजेंसी (सारा) के गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शीघ्र ही मुख्य सचिव के स्तर पर इसका प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव मंजूरी के लिये कैबिनेट में भेजा जाएगा।
- जलागम प्रबंधन को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। एकीकृत एजेंसी बनने से नौले-धारों के उद्धार पर काम करने वाले विभिन्न विभाग एक अंब्रेला के नीचे एक साथ काम कर पाएंगे।
- सारा के गठन के बाद इसमें राज्य स्तर पर एक हाईपावर समिति, ज़िलों में जनपद स्तरीय एग्जीक्यूटिव समिति और गांव स्तर पर धारा-नौला संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा।
- ये समितियाँ राज्यभर के सभी नौले-धारों के साथ वर्षा आधारित नदियों की मैपिंग करेंगी। फिर संवेदनशील जल स्रोतों का चिन्हीकरण, चेकडैम का निर्माण, वर्षा जल संरक्षण के लिये पौधों का रोपण, चाल-खाल का निर्माण जैसे कार्य होंगे। इसके लिये जनसमुदाय को भी इनके उपचार में सहभागी बनाया जाएगा।
- उत्तराखंड उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को सिंचित करने वाली अपनी अनेक सदानीरा नदियों के लिये जाना जाता है। प्रदेश में ग्लेशियर से निकलने वाली और बरसाती को मिलाकर कुल 213 नदियों का विस्तृत जाल है।
- नौले-धारे और कई जलस्रोतों का पानी इन नदियों में मिलकर प्रवाह बढ़ाता है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार, प्रदेश में करीब 12 हज़ार जल स्रोत सूख चुके हैं, जो भविष्य के लिये बड़ी चिंता का विषय है।
- अभी तक प्रदेश में वन, नियोजन, वित्त, कृषि, ग्राम्य विकास, पेयजल, सिंचाई, लघु सिंचाई, राजस्व, पंचायती राज और शहरी विकास विभाग के साथ गैर-सरकारी संस्थाएँ नौले-धारों को बचाने की दिशा में अपने-अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं।
- ज्ञातव्य है कि बीते दिनों मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु के स्तर पर इस मुद्दे पर चिंता जताई गई थी। फिर नौले-धारों व अन्य जलस्रोतों को संरक्षित, पुनर्जीवित करने को एकीकृत एजेंसी का विचार सामने आया। अब इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। एजेंसी के बनने से जल संरक्षण की दिशा में बेहतर ढंग से काम हो सकेगा।

उत्तराखंड में 28 नवंबर से होगा 6वाँ वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारवार्ता कर जानकारी दी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आगामी 28 नवंबर से एक दिसंबर तक 6वाँ वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सम्मेलन में कई देशों और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सम्मेलन के ब्रांड एंबेसडर होंगे।
- सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश और दुनिया भर के विशेषज्ञों के बीच मंथन होगा। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन के विषयों पर चर्चा होगी।
- इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना एवं उनका समाधान करना है।
- सम्मेलन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों में आपदा प्रबंधन के विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा।
- 28 नवंबर को उद्घाटन सत्र होगा। वहीं, सम्मेलन में चार सत्र होंगे, जिसमें 50 टेक्निकल सत्र होंगे। सम्मेलन में कई देशों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक शामिल होंगे।
- आपदा प्रबंधन विभाग इसे लेकर मेगा शो का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा।

मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का हुआ उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के सुरम्य शहर मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में 23 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बने सर जॉर्ज एवरेस्ट संग्रहालय का उद्घाटन और हेलीपैड का उद्घाटन किया।
- पर्यटन मंत्री ने देश के पहले मानचित्रण संग्रहालय को महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर और पंडित नैन सिंह रावत को समर्पित किया।
- विदित है कि संग्रहालय पार्क एस्टेट में स्थित है, जो प्रसिद्ध सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट का निवास स्थान हुआ करता था, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। यह पहाड़ी शहर के हाथीपाँव क्षेत्र में है। सर एवरेस्ट इस घर में 1832 से 1843 तक रहे थे और यह मसूरी में बने पहले घरों में से एक है।

नोट :

- 1832 में बने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायता से, पर्यटन विभाग ने 23.5 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसका नवीनीकरण किया है।
- संग्रहालय में मानचित्रकला के इतिहास, मानचित्रकला से संबंधित उपकरणों, महान भारतीय सर्वेक्षणकर्त्ताओं और महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी गई है।
- इस म्यूजियम में सर जॉर्ज एवरेस्ट के साथ ही सर्वेयर नैन सिंह रावत के पत्रों को भी रखा जाएगा। इसके साथ ही सर्वेयर किशन सिंह नेगी, गणितज्ञ राधानाथ सिकदर की ऑब्जर्वेटरी से भी लोग रूबरू होंगे।
- कार्टोग्राफिक म्यूजियम में पर्यटक जीपीएस की कार्यप्रणाली भी जान पाएंगे, जिसके लिये ग्लोब तैयार किया गया है। म्यूजियम को आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है, जैसे कि सैटेलाइट कैसे काम करते हैं? उनमें जीपीएस और संचार प्रणाली कैसे ऑपरेट की जाती है? इसकी जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी।
- इस म्यूजियम में आने वाले पर्यटक जिस उपकरण के सामने खड़े होंगे, उसकी पूरी जानकारी डिस्प्ले हो जाएगी, जिसे विशेष सॉफ्टवेयर के ज़रिये संचालित किया जाएगा तथा क्यूआर कोड स्कैन करते ही सारी जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि कार्टोग्राफी खोज करने और मानचित्र बनाने के बारे में है। यह वास्तविक या काल्पनिक स्थानों को दिखाने के लिये विज्ञान, कला और तकनीकी कौशल का उपयोग करता है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि चीज़ें कहाँ स्थित हैं।

देहरादून में चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव-2023 का हुआ उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

3 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में चौथे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव-2023 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस उत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईटीएस) ने किया है और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में एकलव्य विद्यालय संगठन समिति (ईवीएसएस), उत्तराखंड इसकी मेज़बानी कर रहा है।

नोट :

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) सांस्कृतिक उत्सव आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने के लिये एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
- इस वर्ष चार दिवसीय कार्यक्रम (3-6 अक्तूबर) में 22 राज्यों के 2000 से अधिक आदिवासी छात्र प्रदर्शन करेंगे।
- उत्सव में 20 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, जिनमें नृत्य और गीत प्रदर्शन से लेकर प्रश्नोत्तरी एवं दृश्य कला आदि शामिल हैं। आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिये विभिन्न राज्यों के स्टॉलों की व्यवस्था की गई है।
- इस तरह के आयोजन ईएमआरएस के बच्चों एवं शिक्षकों को एक-दूसरे से मिलने, देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की कल्पना को पूरा करते हैं।
- इस तरह के कार्यक्रम सभी को प्रेरित करेंगे और अपनी संस्कृति के साथ-साथ देश के विभिन्न कोनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की समृद्ध परंपराओं के बारे में जानने का बेहतर अवसर प्रदान करेंगे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आदिवासियों की विविध परंपराओं और संस्कृति एवं राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये चलाई जा रहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला।
- उल्लेखनीय है कि ईएमआरएस में शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों के लिये 'ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव' हर साल सबसे प्रतीक्षित कार्यक्रम है।
- एनईएसटीएस पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिये ईएमआरएस चला रहा है। ईएमआरएस योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और इसे वर्ष 2018-19 में नया रूप दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूर-दराज के आदिवासी इलाकों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

नोट :

नोट :

वैश्विक निवेशक सम्मेलन: दिल्ली रोड शो में 19,385 करोड़ रुपए के निवेश पर करार

चर्चा में क्यों ?

4 अक्तूबर, 2023 को वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये नई दिल्ली में हुए रोड शो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19,385 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू के तहत जेएस डब्ल्यू एनर्जी 1500 मेगावाट क्षमता के अल्मोड़ा में दो पंप स्टोरेज परियोजनाएँ स्थापित करने में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसे अगले पाँच से छह वर्षों में विकसित किया जाएगा।
- अल्मोड़ा के जोसकोटे गाँव में साइट-एक में यह योजना निचला बांध-जलाशय कोसी नदी से आठ से 10 किमी. की दूरी पर प्रस्तावित है।
- इसके अलावा अल्मोड़ा के कुरचौन गाँव में साइट-दो में यह ऊपरी जलाशय कोसी नदी से 16 किमी. की दूरी पर प्रस्तावित है।
- इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति व कृषि के लिये सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही 1000 लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।
- इसके अलावा, यथार्थ हॉस्पिटल ने चिकित्सा में, डीएस ग्रुप ने फूड प्रोसेसिंग में, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में, रेडिशन ग्रुप ने होटल में, ओबरॉय समूह ने रिसॉर्ट में, एसएलएमजी ने वेलनेस में और कोमयूस्म, टीडब्ल्यूआई, बीएसएस ने कुल 4385 करोड़ रुपए के एमओयू किये। इससे प्रदेश में हज़ारों लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- विदित है कि लंदन, बर्मिंघम, नई दिल्ली में हुए रोड शो में अब तक 40 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश पर करार हुआ है।
- रोड शो में निवेशकों के साथ हुआ करार वैश्विक निवेशक सम्मेलन की सफलता को दर्शाता है। इससे राज्य में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट, ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल, कुमाऊँ के प्राचीन मंदिरों में अवस्थापना विकास, सौंदर्यीकरण के लिये मानसखंड मंदिर माला मिशन में सीएसआर के तहत सहयोग मिलेगा।

नोट :

समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप, स्विटज़रलैंड के मध्य किया गया समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

5 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप, स्विटज़रलैंड के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान के लिये राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी एवं स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिराज आर्टिनियन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- स्विस एजुकेशन ग्रुप द्वारा राज्य में विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में भी सहयोग दिया जाएगा।
- स्विस एजुकेशन ग्रुप की फैकल्टी द्वारा स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में भी स्विस एजुकेशन ग्रुप द्वारा राज्य के स्कूली बच्चों को इन क्षेत्रों में एक-एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- यह समझौता आने वाले समय में राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण के लिये मील का पत्थर साबित होगा।
- विदित है कि राज्य में इन दोनों क्षेत्रों में रोज़गार की काफी संभावनाएँ हैं। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण से दक्षता हासिल करने के पश्चात् विद्यार्थियों को रोज़गार के अनेक अवसर मिलेंगे। इसीलिये राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
- धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के साथ ही ईको टूरिज्म, वैलनेस को बढ़ावा देने के लिये अनेक कार्य किये जा रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में भी राज्य को काफी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस क्षेत्र में भी आने वाले समय में राज्य में अनेक संभावनाएँ हैं।

नोट :

49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस

चर्चा में क्यों ?

7-8 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में दो-दिवसीय 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कार्यक्रम में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस का कम्पेन्डियम, BPR-D की प्रतिष्ठित हिन्दी पत्रिका (पुलिस विज्ञान) और उत्तराखंड पुलिस-मार्चिंग विद द टाइम्स पत्रिका का विमोचन किया।
- इस साइंस कॉन्ग्रेस का उद्देश्य पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करना है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
- उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सम्मेलन अमृतकाल में हो रही पहली पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस है।
- इस पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस के दौरान छह विषयों - 5जी युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स- एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, सोशल मीडिया की चुनौतियाँ, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ तथा पुलिस और CAPFs के बीच समन्वय-सीमाओं की सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया गया।

नोट :

उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 24वीं बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।
- बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और केंद्रीय गृह सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय की सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
- अपने अध्यक्षीय संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार से बदलकर action platform के रूप में कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का देश के जीडीपी और विकास में बहुत बड़ा योगदान है।
- अमित शाह ने कहा कि सहकारी संघवाद के तहत क्षेत्रीय परिषदों ने समस्याओं का समाधान निकालने, financial inclusion बढ़ाने और नीतिगत बदलावों में catalyst की भूमिका निभाई है।
- विदित है कि 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों की 11 और स्थायी समितियों की 14 बैठकें हुईं, जबकि 2014 से 2023 तक क्षेत्रीय परिषदों की 25 और स्थायी समितियों की 29 बैठकें हुई हैं।
- 2004 से 2014 के बीच कुल 570 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 448 को सुलझा लिया गया, जबकि 2014 से 2023 के बीच कुल 1315 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 1157 मुद्दों को सुलझा लिया गया।

नोट :

मुख्यमंत्री ने रोज़गार प्रयाग पोर्टल और 'युवा उत्तराखंड एप' को लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

10 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित 'उत्तराखंड युवा महोत्सव-2023' कार्यक्रम में रोज़गार प्रयाग पोर्टल और 'युवा उत्तराखंड एप'लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोज़गार केंद्रों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोज़गार मेलों के माध्यम से चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।

नोट :

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोज़गार प्रयाग पोर्टल से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी और आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी, वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के पदों की सूचना भी युवाओं को मिल सकेगी।
- प्रदेश के कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिये युवाओं का कौशल विकास ज़रूरी है। इसी सोच के साथ युवाओं को कौशल विकास और रोज़गार से जोड़ने के लिये युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से युवाओं को सभी जानकारियाँ मिल सके, इसलिये सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं।

नोट :

बुलेट रिकवरी बॉक्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में देहरादून में संपन्न हुए ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्ग्रेस में मोहाली की एक कंपनी ने बैलेस्टिक जाँच के लिये तैयार 'बुलेट रिकवरी बॉक्स'नाम के उपकरण को लॉन्च किया, जिससे महज 30 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि गोली किस हथियार से चली है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि गोली चलने की घटनाओं के बाद पुलिस मौके से खाली खोखे और हथियार (बंदूक, पिस्तौल, तमंचा आदि) बरामद करती है। इसके बाद इस बात की जाँच की जाती है कि गोली इस संबंधित हथियार से ही चली है या फिर किसी और हथियार से।
- कई बार मौके से हथियार बरामद न होने की सूरत में दूसरे संदिग्ध हथियारों को भी अपराधियों की निशानदेही पर बरामद किया जाता है। इनकी भी जाँच की जाती है। इस उपकरण की मदद से बैलेस्टिक जाँच के परिणामों में अब लंबा समय नहीं लगेगा।
- फॉरेंसिक लैब में होने वाली जाँच को बैलेस्टिक जाँच कहते हैं। हथियारों के बैरल (नली) में एक विशेष निशान (विज्ञान की भाषा में 'सिग्नेचर') होता है, जो हरेक हथियार में अलग होता है। जब गोली चलती है तो यह निशान गोली पर आ जाता है। इसी निशान को खोजने के लिये फिर से फॉरेंसिक लैब में संबंधित हथियार से फायर किया जाता है।
- इसके बाद देखा जाता है कि क्या ये वही निशान हैं, जो घटनास्थल पर मिली गोली पर हैं। हत्या के मामले में शरीर से गोली निकालकर भी इसे फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। इससे पुष्टि हो जाती है कि गोली इस हथियार से चली या किसी और से।
- अभी तक यह टेस्ट रुई से भरे बॉक्स में फायर कर किये जाते हैं। इसमें गोली ढूंढने में ही घंटों का वक्त लग जाता है। यही नहीं, रुई के रेशों के कारण गोली पर निशान भी ठीक से नहीं आ पाते। ऐसे में सटीक परिणामों के लिये बार-बार फायर किये जाते हैं।
- नया बुलेट रिकवरी बॉक्स पानी से भरा होगा। इसमें गोली के वेग को कम करने के लिये विशेष उपकरण भी लगे हुए हैं। इससे महज 30 सेकंड में ही गोली खुद ब खुद बाहर आ जाएगी और सटीक परिणाम मिल जाएंगे।
- इस उपकरण को प्रायोरिटी सोल्यूशन मोहाली ने विकसित किया है। प्रायोरिटी सोल्यूशन के एमडी गुरुसेवक सिंह ने बताया कि अभी तक पूरे देश में फॉरेंसिक साइंस लैब में रुई आधारित बुलेट रिकवरी बॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। पानी से भरे इस उपकरण को बनाने वाली भारत की यह अकेली कंपनी है। कई देशों में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनकी कंपनी का यह बॉक्स उनसे भी एडवांस है।

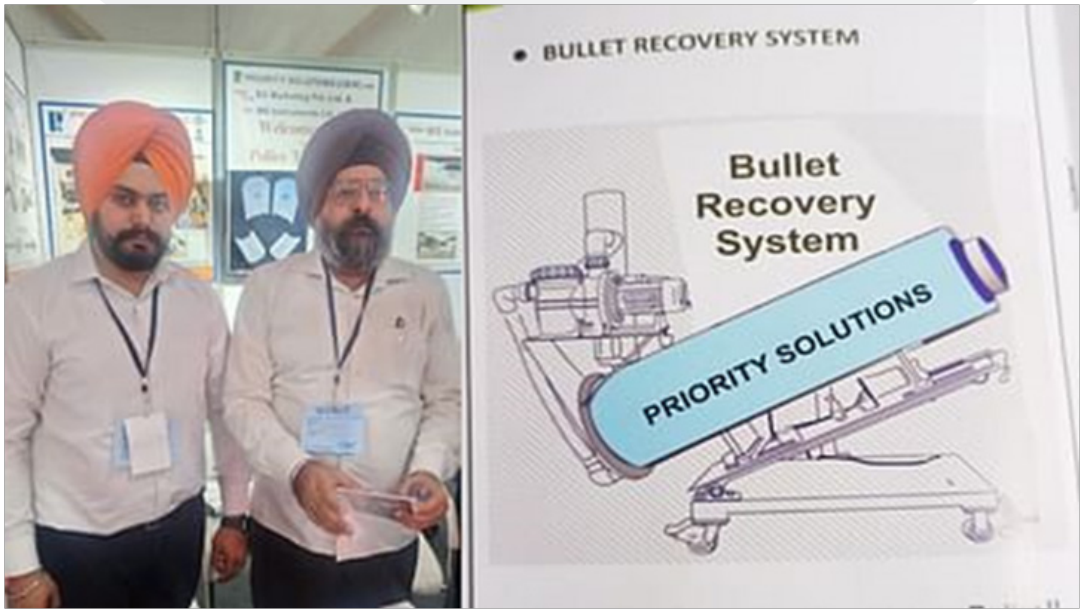

नोट :

प्रदेश में पहली बार पर्यटक स्थलों का कराया जाएगा सर्वे

चर्चा में क्यों ?

10 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन के लिये देश-दुनिया से आने वाले पर्यटकों का पहली बार सर्वे किया जाएगा। सर्वे से प्राप्त होने वाला डाटा भविष्य में पर्यटन विकास योजना बनाने में मददगार साबित होगा।

प्रमुख बिंदु

- युगल किशोर पंत ने बताया कि सर्वे के दौरान पर्यटकों से कई सवालों पर जवाब लिया जाएगा। विदेशी और घरेलू पर्यटकों को राज्य में घूमने-फिरने के लिये सबसे ज्यादा कौन-सा स्थान पसंद है? साथ ही धार्मिक व साहसिक समेत अन्य किन पर्यटन गतिविधियों के लिये उत्तराखंड आते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है? इसे जानने के लिये प्रदेश भर में अलग-अलग पर्यटन स्थलों पर सर्वे किया जाएगा।
- हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, भीमताल, लैंसडाउन, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी समेत प्रदेश के कई पर्यटक स्थलों पर सर्वे कराया जाएगा।
- गौरतलब है कि हर साल लगभग पाँच करोड़ पर्यटक उत्तराखंड आते हैं। इनमें चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्री भी शामिल हैं। गर्मियों की छुटियाँ बिताने, वीकेंड, नए साल का जश्न, राफ्टिंग, पर्वतारोहण, अध्यात्म के लिये देश-विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं।

नोट :

उत्तराखंड में होगा एसआईएसएफ और पर्यटन पुलिस का गठन

चर्चा में क्यों?

10 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और पर्यटक स्थलों की सुरक्षा के लिये राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) और पर्यटन पुलिस के गठन हेतु स्पष्ट प्रस्ताव देने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। राज्य सरकार इन दोनों प्रस्तावों को मंज़ूरी के लिये केंद्र सरकार को भेजेगी।
- बैठक में उन प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई थी, जो गृह मंत्रालय में विचाराधीन हैं। इन सभी प्रस्तावों पर गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद अपर मुख्य सचिव (एसीएस) राधा रतूड़ी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
- बैठक में एसीएस ने नशीले पदार्थों के तस्करों से कड़ाई से निपटने के लिये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पूरी तरह से गठन के निर्देश दिये। टास्क फोर्स में 40 पदों का प्रावधान है, लेकिन एक भी पद नहीं भरा है।
- नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ने और अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पटाक्षेप करने के लिये राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का सहयोग लिया जाएगा।
- एसीएस ने बैठक में वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रस्ताव जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिये। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को क्वालिटी ट्रेनिंग दिये जाने पर बल दिया था, जिसके संबंध में एसीएस ने अधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।
- बैठक में एसीएस ने केंद्र में लागू मॉडल जेल मैनुअल और मॉडल जेल एक्ट 2023 को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कतिपय संशोधन के साथ लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने मॉडल फायर बिल के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से समयबद्ध रूप से प्राप्त करने को कहा।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में लगभग 4200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की

चर्चा में क्यों?

12 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग 4200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कीं।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं का उद्घाटन व राष्ट्र को समर्पित किया गया-
  - पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 76 ग्रामीण सड़कें और 25 पुल;
  - 9 ज़िलों में बीडीओ कार्यालयों के 15 भवन;
  - केंद्रीय सड़क निधि के तहत निर्मित तीन सड़कों- कौसानी-बागेश्वर रोड, धारी-दौबा-गिरिछीना रोड और नगला-किच्छा रोड का उन्नयन;
  - राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो सड़कों- अल्मोड़ा पेटशाल-पनुवानौला-दन्या (एनएच 309बी) और टनकपुर-चल्थी (एनएच 125) का उन्नयन;
  - पेयजल से संबंधित तीन परियोजनाएँ- 38 पंपिंग पेयजल योजनाएँ, 419 गुरुत्वाकर्षण पर आधारित जलापूर्ति योजनाएँ और तीन ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाएँ;
  - पिथौरागढ़ में थरकोट कृत्रिम झील;

नोट :

- 132 केवी पिथौरागढ़-लोहाघाट (चंपावत) पावर ट्रांसमिशन लाइन;
- उत्तराखंड में 39 पुल और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के तहत देहरादून में बनाई गई उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) की इमारत।

- जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, वे हैं-
  - 21,398 पॉली-हाउस के निर्माण की योजना, जिससे फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी;
  - उच्च घनत्व वाले सघन सेब के बगीचों की खेती के लिये एक योजना;
  - राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के उन्नयन के लिये पाँच परियोजनाएँ
  - राज्य में आपदा तैयारियों और सुदृढ़ता के लिये कई कदम- पुलों का निर्माण, देहरादून में स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का उन्नयन, बलियानाला व नैनीताल में भूस्खलन की रोकथाम के लिये कदम तथा आग, स्वास्थ्य एवं वन से संबंधित अन्य बुनियादी ढाँचे में सुधार;राज्य भर के 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों में छात्रावास एवं कंप्यूटर लैब का विकास;
  - अल्मोड़ा के सोमेश्वर में 100 बिस्तरों वाला उप ज़िला अस्पताल;
  - चंपावत में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल ब्लॉक;
  - नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान;
  - रुद्रपुर में वेलोड्रोम स्टेडियम;
  - जागेश्वर धाम (अल्मोड़ा), हाट कालिका (पिथौरागढ़) और नैना देवी (नैनीताल) मंदिरों सहित विभिन्न मंदिरों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये 'मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना।

नोट :

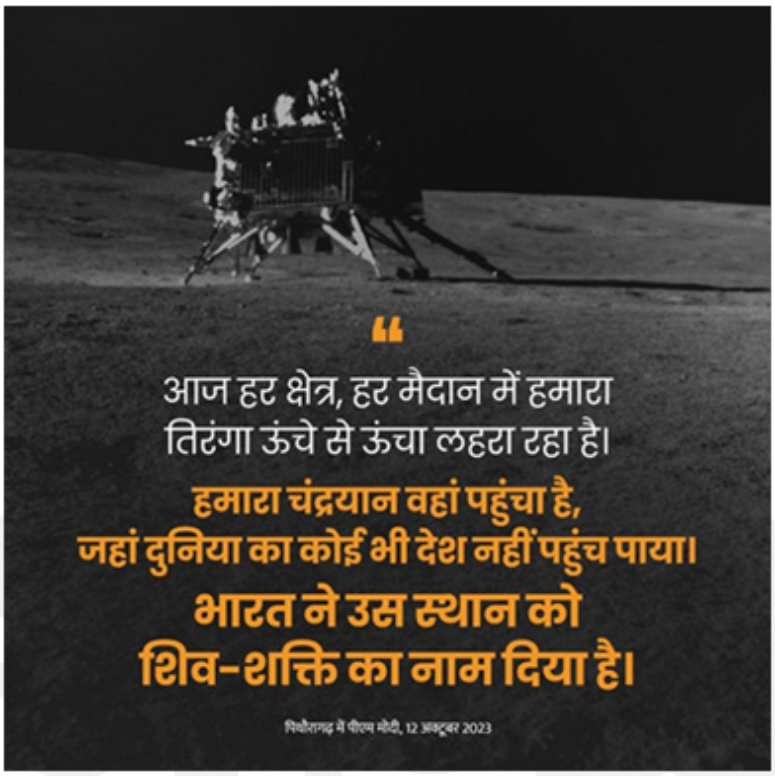
“
आज हर क्षेत्र, हर मैदान में हमारा
तिरंगा ऊंचे से ऊंचा लहरा रहा है।
हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा है,
जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया।
भारत ने उस स्थान को
शिव-शक्ति का नाम दिया है।
पिथौरागढ़ में पीएम मोदी, 12 अक्टूबर 2023

“
स्पोर्ट्स में भी भारत का दम आज दुनिया देख रही है।
हाल में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं।
इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने 100 से
ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है।
पिथौरागढ़ में पीएम मोदी, 12 अक्टूबर 2023

नोट :

“
उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं।
वन रैंक वन पेंशन की उनकी
दशकों पुरानी मांग को
हमारी ही सरकार ने पूरा किया है।
पिथौरागढ़ में पीएम मोदी, 12 अक्टूबर 2023

“
हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं,
बल्कि देश के पहले गांव के
रूप में विकसित करना शुरू किया है।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, ऐसे ही
सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है।
पिथौरागढ़ में पीएम मोदी, 12 अक्टूबर 2023

नोट :

‘ऐपण महोत्सव’ का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 अक्तूबर, 2023 को हरिद्वार बाईपास स्थित उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद के सभागार में लोक संस्कृति ऐपण कला को बढ़ावा देने के लिये उत्तराखंड की संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की ओर से ‘ऐपण महोत्सव’ का शुभारंभ किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- महोत्सव के शुभारंभ पर वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से 15 अक्तूबर से 12 नवंबर को दीपावली तक ऐपण महोत्सव मनाने का आह्वान किया और कहा कि सामूहिक प्रयास से ऐपण कला को वैश्विक पटल पर पहचान मिलेगी।
- वीडियो संदेश में सीएम ने कहा कि ऐपण कला लोक संस्कृति की विधा है। परिवार की सुख-समृद्धि के लिये घर की दीवारों और देहरियों पर ऐपण बनाया जाता है।
- राज्य सरकार का प्रयास है कि इस कला को देश-दुनिया तक पहुँचाया जाए। इसके लिये सामूहिक प्रयास से ऐपण को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने आह्वान किया कि दीपावली तक ऐपण हर घर का हिस्सा बने। इसके लिये लोग अपने घरों पर ऐपण बनाकर परिवार के साथ सेल्फी को सोशल मीडिया पर अपलोड करें।
- संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि दीपावली तक पूरे प्रदेश में ऐपण महोत्सव मनाया जाएगा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये युवा पीढ़ी भी अपनी गढ़वाल, कुमाऊँनी, जौनसारी बोली को बोले। युवाओं को ऐपण कला से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

नोट :

37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड से 18 खेलों में 140 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग

चर्चा में क्यों ?

15 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने गोवा में 26 अक्तूबर से शुरू हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी। उत्तराखंड से 18 खेलों में 140 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार के मुताबिक ओलंपिक एसोसिएशन, राष्ट्रीय खेलों के लिये खिलाड़ियों का चयन कर इसकी सूची तैयार करती है। जो व्यवस्था अन्य प्रदेशों में है, ठीक वही व्यवस्था उत्तराखंड में है।
- गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड से कयाकिंग और कैनोइंग में 13, साइकिलिंग में एक, तैराकी में छह, वुशु में चार, भारोत्तोलन में दो, जूडो में छह, ताइक्वांडो में सात, मिनी गोल्फ में 20, योगा में 10, शूटिंग में तीन, फुटबॉल में 12, बॉक्सिंग में 10, पेनकैकसिल्ट में सात,सेपकटकरा छह, एथलेटिक्स में 14, बैडमिंटन में 11, तीरंदाज़ी में छह, गोल्फ में दो खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। वहीं 47 कोच व स्टाफ भी गोवा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुमाऊँ यात्रा में बना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

15 अक्तूबर, 2023 को संस्कृति विभाग की निदेशक बीना भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के कुमाऊँ दौरे के दौरान एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। उत्तराखंड संस्कृति विभाग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का प्रोविजनल प्रमाणपत्र भी मिल चुका है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊँ दौरे पर कुमाऊँ के छोलिया और झोड़ा लोक नृत्य के ढोल दमाऊँ लोक वाद्यों के साथ की गई प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है।

नोट :

- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में समुद्र सतह से 5338 फीट (1627 मीटर) की ऊँचाई पर 12 अक्तूबर को संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस अनोखे आयोजन में प्रदेश के तीन हज़ार लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा व लोकगीतों के साथ हिस्सा लिया था।
- पिथौरागढ़ के सुदूरवर्ती अंचलों से छोलिया एवं झोड़ा नृत्य दल के इन कलाकारों की प्रस्तुति से विश्व का ध्यान राज्य की ऐतिहासिक और समृद्धशाली लोक सांस्कृतिक विरासत की ओर गया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के दौरान छोलिया एवं झोड़ा नृत्य दलों के लोक कलाकार अपने पारंपरिक परिधानों और आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रतिभाग करने पहुँचे थे। इस आयोजन के दौरान पारंपरिक लोक वाद्यों, जैसे- तुन, रणसिंघा लिये कलाकार आकर्षक लग रहे थे।

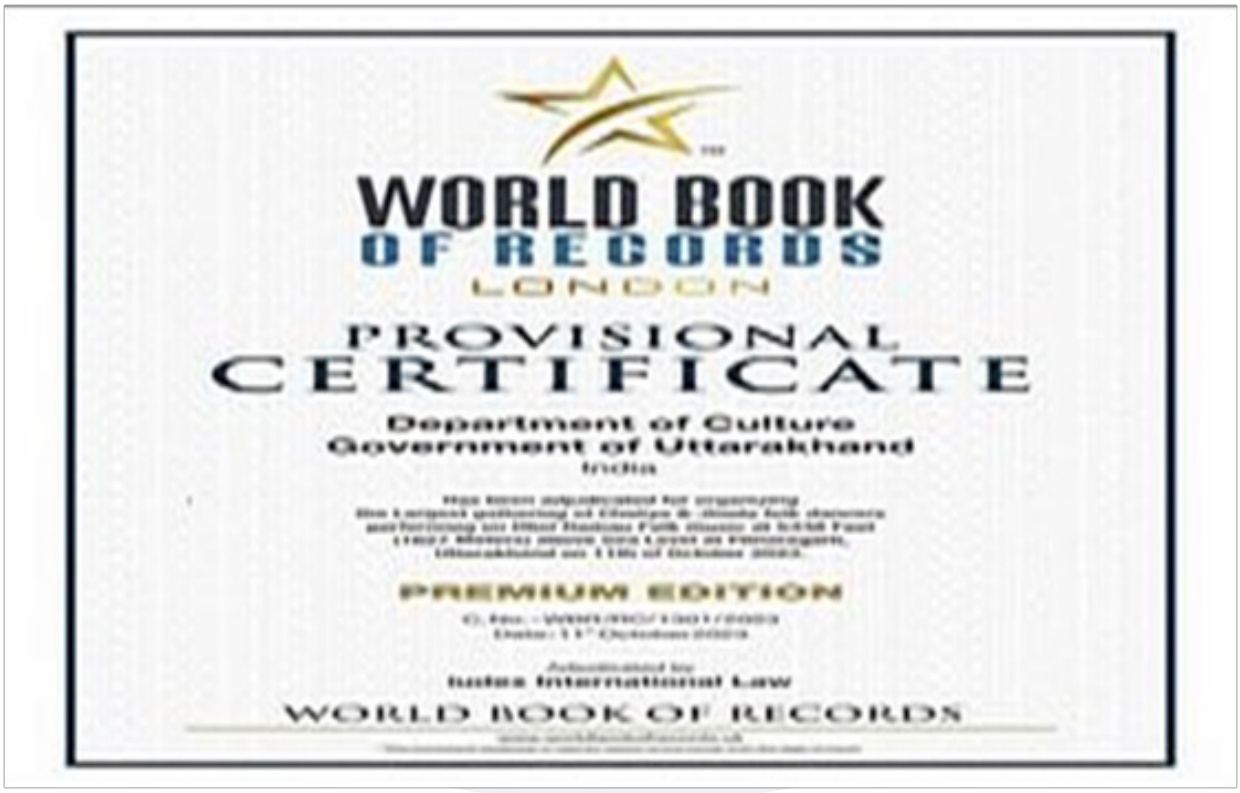

नोट :

मुख्यमंत्री ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के कार्यालय का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 अक्तूबर, 2023 को दून बिज़नेस पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में टेक्नोलॉजी के साथ व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का यह कार्यालय आईटी सेवाओं के विस्तार में मील का पत्थर साबित होगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश तेज़ी से प्रगति कर रहा है। यह क्षेत्र सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है और लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नया भारत, टेक्नोलॉजी का न सिर्फ कंज्यूमर है, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास में और उसके क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

नोट :

- 2जी, 3जी, 4जी के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिये दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5जी के साथ ही भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5जी के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत में डिजिटलाइजेशन तेज़ी से हो रहा है।
- डिजिटल भारत देश के विकास के विस्तृत विज़न का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इस विज़न का लक्ष्य है- उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुँचाना, जो लोगों के लिये काम करे, लोगों के साथ जुड़कर काम करे।
- उन्होंने कहा कि आज छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी, कारीगर, सबको डिजिटल भारत ने एक मंच प्रदान किया है, एक बाज़ार उपलब्ध कराया है। बाज़र में, मंडियों में रेहड़ी-पटरी में कार्य कर रहे लोग, सब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उत्तराखंड खेल महाकुंभ 2023

चर्चा में क्यों ?

16 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि हर साल अक्तूबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले उत्तराखंड खेल महाकुंभ को इस बार 31 अक्तूबर से दिसंबर आखिर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेल महाकुंभ के लिये स्थान चयन, मुख्य अतिथि और आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में जल्द स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।
- चार लाख से अधिक प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करेंगे, जिसमें पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि दी जाएगी।
- खेल महाकुंभ में ब्लॉक से राज्य स्तर तक होने वाली प्रतियोगिताओं में पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है। ब्लॉक स्तर पर पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पाँच सौ रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को चार सौ रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले को तीन सौ रुपए की राशि दी जाएगी।
- इसके अलावा राज्य स्तर पर भी पुरस्कार की धनराशि बढ़ाई गई है। राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 1500 रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को एक हज़ार रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले को सात सौ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जबकि प्रति खिलाड़ी भोजन की राशि को 225 रुपए किया गया है।

नोट :

उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को फिल्म 'एक था गाँव' के लिये मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

17 अक्तूबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के कीर्तिनगर ब्लॉक के सेमला गाँव निवासी सृष्टि लखेरा को उनकी फिल्म 'एक था गाँव'के लिये बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की केटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2021 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये। उन्होंने वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिये दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया।
- सृष्टि लखेरा ने फिल्म 'एक था गाँव'का प्रोडक्शन और निर्देशन किया है। इससे पहले यह फिल्म मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज (मामी) फिल्म महोत्सव के इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है।
- सृष्टि के पिता एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. केएन लखेरा ने बताया कि सृष्टि करीब 13 साल से फिल्म लाइन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।
- गढ़वाली और हिन्दी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज (पलायन से खाली हो चुके गाँव) की कहानी है। उत्तराखंड में पलायन की पीड़ा को देखते हुए सृष्टि ने यह फिल्म बनाई।
- डॉ. केएन लखेरा ने बताया कि पहले उनके गाँव में 40 परिवार रहते थे और अब पाँच से सात लोग ही बचे हैं। लोगों को किसी-न- किसी मज़बूरी से गाँव छोड़ना पड़ा। इसी उलझन को उन्होंने एक घंटे की फिल्म के रूप में पेश किया है। फिल्म के दो मुख्य पात्र हैं- 80 वर्षीय लीला देवी और 19 वर्षीय किशोरी गोलू।

नोट :

उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वेलनट मिशन शुरू करेगी राज्य सरकार

चर्चा में क्यों ?

17 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में उद्यान विभाग के साथ मिलकर अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये वेलनट मिशन को शुरू किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य की आय में वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी का प्रतिशत बढ़ाने के लिये कई कार्ययोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मिशन वेलनट और नॉन टिंबर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बढ़ावा देना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसमें जड़ी-बूटियों के उत्पादन को भी शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
- एक अनुमान के अनुसार, राज्य की आय में वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2.5 से 3.5 प्रतिशत तक है, जबकि वानिकी क्षेत्र को राज्य की आर्थिकी का प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर चिह्नित किया गया है।
- प्रदेश में वन संपदा को लोगों की आजीविका से जोड़ते हुए कई नए प्रयोग करने की तैयारी है। इसके तहत उच्च हिमालयी क्षेत्रों सहित मैदानी इलाकों के लिये अलग-अलग योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके तहत अखरोट, बांस, बांज, सागोन, पापुलर जैसी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- वन मंत्री ने बताया कि लीसा बिक्री के नियमों में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में लीसा बिक्री की ऑनलाइन व्यवस्था के तहत नीलामी की जाती है, स्थानीय लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के स्तर से स्थानीय स्तर पर लीस ब्रिकी संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिये गए हैं।
- प्रदेश में यूकेलिप्टस प्रजाति के पुराने पेड़ों को काटने के लिये कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश शासन स्तर पर दिये गए हैं। इनके स्थान पर ज़रूरत के अनुसार नई प्रजाति के पौधे भी लगाए जा सकते हैं, जो नॉन टिंबर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की श्रेणी में आते हों।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड अखरोट उत्पादन में देश में जम्मू-कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ अखरोट उत्पादन के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इसके बावजूद बीते कुछ सालों में राज्य में इसका उत्पादन घटा है। राज्य में प्रति वर्ष करीब 18 से 20 हज़ार मीट्रिक टन अखरोट का उत्पादन होता है।
- नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, देहरादून, पौड़ी टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में इसके उत्पादन की अपार संभावनाएँ हैं। यही वजह है कि सरकार अब अखरोट उत्पादन को मिशन मोड में शुरू करने जा रही है।

दुबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 5450 करोड़ रुपए के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन

चर्चा में क्यों ?

17 अक्तूबर, 2023 को दुबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पर्यटन, शिक्षा, इन्फ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े समूहों के साथ 5450 करोड़ रुपए के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किये गए। प्रदेश सरकार की ओर से उद्योग सचिव विनय शंकर पांडेय ने एमओयू पर साइन किये।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेतु दुबई में आयोजित रोड शो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
- मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दुबई में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 5450 करोड़ रुपए के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किये जा चुके हैं, जबकि कई अन्य उद्योग समूहों के साथ बैठक जारी है। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योग घरानों को आगामी 8 एवं 9 दिसंबर में देहरादून में आयोजित होने वाली समिट हेतु निमंत्रण भी दिया।
- दुबई में अब तक सर बायोटेक एवं हयात इंडिया के साथ 2 हज़ार करोड़, कार्मिला न्यूट्रीशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फार्मा प्रोडक्शन हेतु 950 करोड़, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़, फ्लो कॉग्लोमिरेट समूह के साथ रियल एस्टेट, इन्फ्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु 500 करोड़, एक्सले ग्रुप के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेतु 700 करोड़ रुपए एवं शरफ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किये जा चुके हैं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश अनुकूल सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले से और अधिक मज़बूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
- विदित हो कि उत्तराखंड में वैश्विक निवेश आकर्षित करने हेतु दिसंबर, 2023 में 'उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 (डेस्टिनेशन उत्तराखंड)' आयोजित की जा रही है।
- वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये अब तक 40 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू किया जा चुका है। लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में हुए रोड शो में निवेशकों के साथ निवेश पर करार किया गया है। राज्य सरकार ने इस सम्मेलन के लिये 2.50 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है।
- राज्य में औद्योगिक विद्युत दरें भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम है, राज्य में औद्योगिक सद्भाव एवं उत्कृष्ट कानून व्यवस्था इसे और विशेष बनाते हैं। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बेहतर वातावरण प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियाँ, योजनाएँ एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में दो मेगा फूड पार्क एवं चार फूड क्लस्टर बनाए गए हैं, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं।
- ईज आफ डूईंग बिज़नेस की दिशा में राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में है। श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में राज्य ने विशिष्ट पहल की है। इसी प्रकार निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी लगातार सुधार एवं सरलीकरण किया गया है।

नोट :

वीपीकेएएस में 47वाँ कृषि विज्ञान मेले का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

19 अक्तूबर, 2023 को अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएएस) में 47वाँ कृषि विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन सांसद अजय टम्टा ने किया।

प्रमुख बिंदु

- 'श्री अन्न अपनाएँ पोषण सुरक्षा बढ़ाएँ'थीम पर इस मेले का आयोजन किया गया।
- सांसद अजय टम्टा ने कहा कि संस्थान ने शोध कार्यों विशेषरूप से मृदा परीक्षण, रोग-कीट नियंत्रण, फसल उत्पादन, सफेद मंडुवा उत्पादन के साथ ही प्रसंस्करण, तकनीकी विकास के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने उत्पादित बीज व तकनीकी भारत के 24 राज्यों में पहुँचाने की प्रशंसा की।
- जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के निदेशक डॉ. जय प्रकाश जायसवाल ने संस्थान की प्रजाति एवं लघु यंत्रों के विकास के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इसके महत्त्व को बताया।
- इस अवसर पर वीएल पालीटनल के निर्माण हेतु संस्थान तथा परासर एग्रोटेक बायो प्राईवेट लिमिटेड, वाराणसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- कृषि विज्ञान मेले में संस्थान में विकसित गेहूँ की वीएल कुकीज, सब्जी मटर की वीएल उपहार तथा मसूर की वीएल मसूर 150 का लोकार्पण किया गया। सीआईएई वीएल मल्टीक्रॉप थ्रेशर का भी लोकार्पण किया गया।

बिल लाओ इनाम पाओ योजना: विजेताओं को वित्त मंत्री ने दिये पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

19 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड कर विभाग की 'बिल लाओ इनाम पाओ योजना' के अप्रैल और मई माह में निकाले गए लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

- राज्य कर मुख्यालय में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लकी ड्रॉ के 100 विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच तथा ईयर पॉड वितरित किये।

नोट :

- उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल लेने के लिये जागरूक करने के उद्देश्य से एक सितंबर, 2022 से 'बिल लाओ इनाम पाओ योजना' चलाई जा रही है। योजना के तहत अब तक सात मासिक लकी ड्रॉ निकाले गए हैं।
- इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि सितंबर 2022 से अब तक योजना में 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। इनके माध्यम से 2,10,382 बिल अपलोड किये गए। इन बिलों में सामान खरीद का कुल मूल्य 82.60 करोड़ रुपए है। इस साल एक अप्रैल से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिन्होंने 41.28 करोड़ रुपए के 1,23,467 बिल अपलोड किये।
- उन्होंने बताया कि 'बिल लाओ इनाम पाओ योजना'31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रही थी, जिसे सरकार ने नवंबर तक बढ़ा दिया है। 30 नवंबर के बाद मेगा पुरस्कार भी दिये जाएंगे। इसके अलावा अपलोड किये प्रत्येक बिल पर कस्टमर रिवॉर्ड प्रोग्राम लागू कर हर अपलोडेड बिल पर पॉइंट्स देने की व्यवस्था है। योजना में उन व्यापारियों को पुरस्कार दिया जाएगा।

नोट :

देश में कुल उत्पादन का 20 फीसदी दवाएँ बना रहा प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

18 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने बताया कि देश में कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत दवाइयाँ उत्तराखंड बना रहा है। औषधि निर्माण में राज्य देश का प्रमुख हब के रूप में विकसित हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने बताया कि नई औद्योगिक नीति और अनुकूल माहौल से राज्य में फार्मा सेक्टर में निवेश के साथ कारोबार लगातार बढ़ रहा है। देश में निर्मित होने वाली कुल दवाओं के उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है।
- 2022 में राज्य के फार्मा सेक्टर ने 15 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसमें 1150 करोड़ रुपए की दवाइयाँ निर्यात की गईं।
- उन्होंने बताया कि हरिद्वार, सेलाकुई और पंतनगर में 249 ड्रग्स निर्माता फार्मा कंपनियाँ हैं। विभाग का प्रयास है कि इन कंपनियों में उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का उत्पादन हो, साथ ही देश में कंपनियों की दवाओं का शेयर भी बढ़े।
- औद्योगिक नीति के तहत एकल खिड़की योजना के तहत उद्योगों को ऑनलाइन अनुमति दी जाती है। प्रदेश में मानकों के तहत उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का निर्माण करने के लिये औषधि नियंत्रण विभाग सतर्क रहता है और समय-समय पर दवाओं की गुणवत्ता और मानकों की जाँच की जाती है।
- ताजबर सिंह ने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक संगठन के सब ज़ोन ऑफिस उत्तराखंड में स्थापित हैं। फार्मा कंपनियों के लिये ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया होने के कारण आवेदन की जटिलता को समाप्त किया गया है। दवाइयों की गुणवत्ता के लिये केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त निरीक्षण करने के बाद लाइसेंस जारी किये जाते हैं।

नोट :

राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव तैयार

चर्चा में क्यों ?

22 अक्तूबर, 2023 को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कार्बेट टाइगर फाउंडेशन की तर्ज़ पर राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे आगामी कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी के लिये रखा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में फाउंडेशन के गठन का फैसला लिया गया था। प्रस्तावों को न्याय और कार्मिक विभाग से हरी झंडी मिल गई है।
- राजाजी टाइगर कंजरवेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य रिज़र्व क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति देने और उन्हें सुगम बनाने का है।
- फाउंडेशन के तहत क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों को आजीविका की ऐसी वैकल्पिक योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जो वनों पर निर्भर हैं। अलग-अलग योजनाओं के ज़रिये उनकी वनों से निर्भरता को कम करने के प्रयास किये जाएंगे, उनकी आर्थिकी में सुधार के लिये ईको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसके अलावा ऐसे उपाय भी किये जाएंगे कि मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान हो सके और वन्यजीवों के शिकार और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगे।
- पर्यावरण शिक्षा में सहयोग के लिये नियमित बजट का प्रावधान भी किया जाएगा। टाइगर रिज़र्व में तैनात कर्मचारियों के कल्याण उनके वन्य आवास सुरक्षा, वन्यजीव सुरक्षा के लिये कदम उठाए जाएंगे।
- फाउंडेशन के तहत एक ट्रस्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका बाकायदा नियमानुसार पंजीकरण कराया जाएगा। इसका एक शासी निकाय होगा। राज्य सरकार फाउंडेशन की कार्यप्रणाली की सुरक्षा कर सकेगी।
- फाउंडेशन के गठन के बाद रिज़र्व एरिया में पर्यटन गतिविधियों से जो आय प्राप्त होगी, उसे राज्य सरकार के राजकोष में जमा कराना होगा। बाद में सरकार फाउंडेशन को अनुदान के रूप में लौटाएगी।

नोट :

सौ करोड़ रुपए से बनाए जाएंगे पुलिसकर्मियों के आवास

चर्चा में क्यों ?

21 अक्तूबर, 2023 को पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों की आवास की समस्या को दूर करने के लिये 100 करोड़ रुपए और ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आर्थिक सहायता के लिये पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में इस वर्ष ड्यूटी के दौरान शहीद हुए उत्तराखंड पुलिस के चार जवानों समेत देश के 188 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि दो देशों और दो राज्यों से सीमाएँ मिलने की वजह से उत्तराखंड संवेदनशील है। यहाँ की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस पर है। कर्त्तव्य के पालन में कई पुलिसकर्मी हर साल शहीद हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में एक लाख रुपए दिये जाते हैं।

नोट :

- कई बार इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है, लिहाजा इस काम को और अधिक सरल करने के लिये पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपए दिये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त पुलिसकर्मियों के सामने आवास की बड़ी समस्या है। बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें आवास मिलता नहीं या फिर थानों व ड्यूटी स्थल से बहुत दूर होते हैं। आवास की इस समस्या को दूर करने के लिये तीन साल के भीतर 100 करोड़ रुपए दिये जाएंगे।

राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन मालसी (देहरादून) में

चर्चा में क्यों ?

23 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मालसी (देहरादून) में पहली बार पंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रतियोगिता 28 अक्तूबर से मालसी (देहरादून) के फुटहिल गार्डन में आयोजित होगी।
- यह प्रतियोगिता नेशनल बॉक्सिंग काउंसिलिंग के बैनरतले आयोजित की जा रही है।
- इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त 20 बॉक्सर प्रतिभाग करेंगे, जिनमें बॉक्सर विकास यादव, पवन कुमार, कमला रोका, नंदनी पाल, अरुण फर्तयाल, रोहन रामेश्वर, रितेश सिहं, मोहम्मद जावेद, कुनाल राजपूत, चंदू जी, मो. अजहर, प्रियारंजन नायक, राकेश लोहचाव, अक्शय चहल, सतनाम सिंह, मोहित,सक्षम ठाकुर, जसकिरण सिंह, अकिलन आन्नदुराई व आरुण शर्मा प्रतिभाग करेंगे।

उत्तरकाशी ज़िले में की जाएगी काले गेहूँ की खेती

चर्चा में क्यों ?

24 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी ज़िले के ज़िलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने डुण्डा ब्लॉक के गेंवला गाँव में काले गेहूँ की खेती से जुड़ने के लिये किसानों को प्रेरित किया और काले गेहूँ के बीज वितरित किये।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सामान्य गेहूँ की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कीमत वाले काले गेहूँ के ज़रिये किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिये ज़िले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है।
- इससे पहले ज़िले में लाल धान को गंगा घाटी तक विस्तारित करने के सफल प्रयास किये गए थे।
- गौरतलब है कि काले गेहूँ की खेती का चलन देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों में शुरू हुआ है।
- काला गेहूँ-
  - काले गेहूँ में फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर नए ऊतकों के बनने में सहायक होता है और इनके रखरखाव में भी अहम भूमिका निभाता है।
  - काले गेहूँ में मौजूद पोषक तत्त्व जैसे प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन मानव शरीर में ब्लड लेवल को बढ़ाकर खून की कमी को दूर करते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को कंट्रोल करते हैं।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना शामिल

चर्चा में क्यों ?

25 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2028 तक 2,584.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना को पूरा करने के लिये उत्तराखंड को 1,557.18 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंज़ूरी दे दी है।
- इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में राम गंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह बांध मौजूदा गोला बैराज को अपनी 40.5 किमी. लंबी नहर प्रणाली और 244 किमी. लंबी नहर प्रणाली के माध्यम से पानी देगा, जो 1981 में पूरा हुआ था।

नोट :

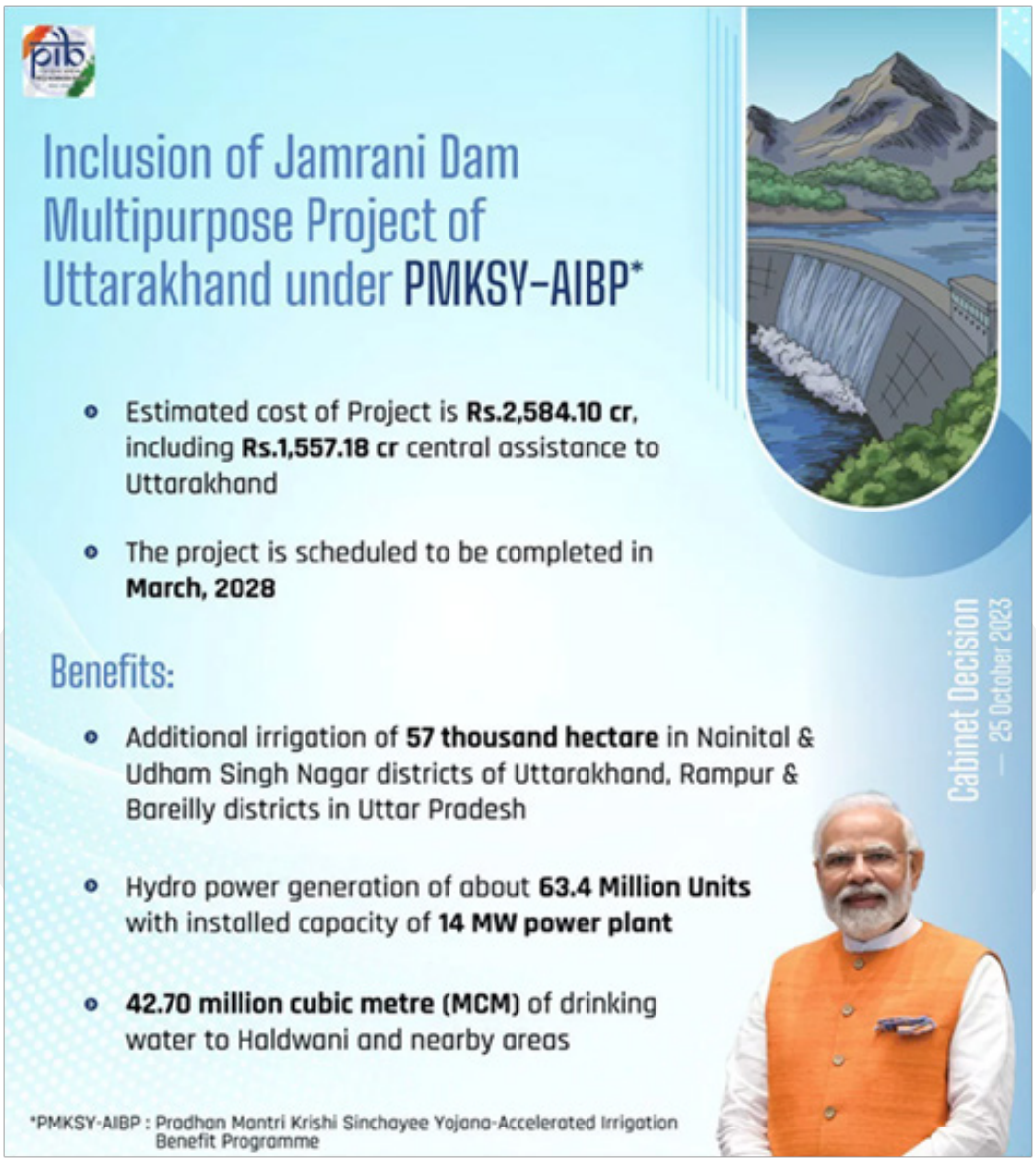

- इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर ज़िलों और उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली ज़िलों में 57,065 हेक्टेयर (उत्तराखंड में 9,458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर) की अतिरिक्त सिंचाई की परिकल्पना की गई है।
- दो नई फीडर नहरों के निर्माण के अलावा, 207 किमी. मौजूदा नहरों का नवीनीकरण किया जाना है और परियोजना के तहत 278 किमी. पक्के फील्ड चैनल भी क्रियान्वित किये जाने हैं।
- इसके अलावा इस परियोजना में 14 मेगावाट के जल विद्युत उत्पादन के साथ-साथ हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पीने के पानी के प्रावधान की भी परिकल्पना की गई है, जिससे 10.65 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी।
- इस परियोजना के सिंचाई लाभों का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को भी होगा और दोनों राज्यों के बीच लागत/लाभ साझाकरण 2017 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसार किया जाना है। हालाँकि, पीने का पानी और बिजली लाभ पूरी तरह से उत्तराखंड के लिये ही परिकल्पित है।

नोट :

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की पहुँच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि है।
  - भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 2021-26 के दौरान पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को रुपए 93,068.56 करोड़ (37,454 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता) के समग्र परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी थी।
  - पीएमकेएसवाई का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता के निर्माण से संबंधित है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत अब तक 53 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं तथा 25.14 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।
  - 2021-22 के बाद पीएमकेएसवाई के एआईबीपी घटक के अंतर्गत अब तक छह परियोजनाओं को शामिल किया गया था। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना एआईबीपी के अंतर्गत शामिल होने वाली सातवीं परियोजना है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

चर्चा मे क्यों ?

25 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- 19 सितंबर, 1965 को पिथौरागढ़ में जन्में जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। वे 1990 में बार काउंसिल ऑफ यूपी इलाहाबाद में पंजीकृत हुए और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रैक्टिस शुरू की।
- 2000 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय बनने पर वह नैनीताल स्थानांतरित हुए। 20 मई, 2009 को उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। वे 2008 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष बने तथा 9 मई, 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने।
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
  - भारत के संविधान का अनुच्छेद-223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है।
  - इसके अनुसार, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त कर सकता है।

महाविद्यालयों को पाँच से 10 लाख रुपए पुरस्कार देगी सरकार

चर्चा में क्यों ?

28 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड राज्य शासन ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को सरकार द्वारा पाँच से 10 लाख रुपए तक पुरस्कार देने के संबंध में आदेश जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने एवं महाविद्यालयों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लिये ग्रेडिंग के हिसाब से यह धनराशि दी जाएगी।

नोट :

- आदेश में कहा गया है कि महाविद्यालयों को पुरस्कार के रूप में मिलने वाली इस धनराशि को उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय छात्रनिधि नियमावली 2020 में दी गई व्यवस्था के तहत ही खर्च किया जा सकेगा।
- पुरस्कार की राशि पिछले साल नैक मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालयों एवं भविष्य में नैक मूल्यांकन वाले महाविद्यालयों को मिलेगी। पुरस्कार के लिये नियमानुसार बजट में व्यवस्था की जाएगी।
- शासन के आदेश के मुताबिक महाविद्यालयों को विभाग के तहत गठित कॉर्पस फंड के माध्यम से यह धनराशि दी जाएगी। बी ग्रेड वाले महाविद्यालयों को पाँच लाख रुपए और ए डबल प्लस वाले महाविद्यालयों को पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
- इसके अलावा ए प्लस ग्रेड पर 9 लाख, एक ग्रेड पर आठ लाख, बी डबल प्लस पर सात और बी प्लस पर छह लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे।
- उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक प्रदेश के 27 महाविद्यालय नैक मूल्यांकन करा चुके हैं। वर्ष 2022-23 में 19 महाविद्यालयों ने नैक मूल्यांकन कराया है।
- नैक मूल्यांकन करा चुके प्रदेश के 27 राजकीय महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय को ए या ए प्लस ग्रेड नहीं मिला है।
- नैक मूल्यांकन करा चुके महाविद्यालयों में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला, महाविद्यालय चौबट्टाखाल, टनकपुर, लोहाघाट, रानीखेत, द्वाराहाट, अगस्त्यमुनि, हल्द्वानी, रामनगर, पिथौरागढ़, काशीपुर, उत्तरकाशी, बेरीनाग, महिला महाविद्यालय हल्द्वानी, नरेंद्रनगर, कोटद्वार भाबर, रायपुर, चकराता, तलवाड़ी, कोटद्वार, पुरोला, त्यूनी, चंद्रबदनी, हल्दूचौड़, बड़कोट व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग शामिल हैं।
- गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पिछले साल हुई विभाग की बैठक में सभी महाविद्यालयों के अनिवार्य रूप से नैक मूल्यांकन के निर्देश दिये थे। मंत्री का कहना था कि मार्च 2023 तक ऐसा न करने वाले अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त की जाएगी, जबकि राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।

उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग के बीच बनेगी कंक्रीट की दीवार

चर्चा में क्यों ?

28 अक्तूबर, 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि देश में पहली बार यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग के बीचोबीच कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- एनएचआईडीसीएल के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि देश में यह पहली सुरंग होगी, जिसके बीच में कंक्रीट की मज़बूत दीवार बनाई जा रही है। इससे गाड़ियाँ अपनी-अपनी लेन में चलेगी और दुर्घटना की आशंका शून्य होगी। हालाँकि, आपातकाल में एक से दूसरी टनल में जाने के लिये दीवार में एयर टाइट दरवाज़े बनाए जाएंगे।
- चारधाम सड़क परियोजना के तहत यमुनोत्री हाईवे पर 850 करोड़ रुपए की लागत से सिलक्यारा से पोल गाँव तक 4.5 किमी. लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जिसका अब 500 मीटर ही निर्माण शेष बचा है।
- इस सुरंग में फायर सप्रेशन सिस्टम और स्काडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजीशन) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाएगा।
- सुरंग के अंदर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये 400 एमएम की एक कंक्रीट की मज़बूत दीवार बनाई जा रही है, जिससे दायीं व बायीं ओर का ट्रैफिक अपनी-अपनी लेन से गुज़रेगा। इस दीवार के कारण सुरंग के अंदर वाहनों के एक-दूसरे से टकराने की आशंका शून्य हो जाएगी।
- सुरंग के अंदर यदि किसी वाहन में कोई खराबी आती है तो उसे ले-बाई (सड़क किनारे कुछ समय के लिये वाहन खड़ा करने का स्थान) की सुविधा मिलेगी। हर 500 किमी. पर एक ले-बाई की सुविधा मिलेगी। सुरंग के दायीं व बायीं, दोनों तरफ कुल सात ले-बाई बनाई जाएंगी, जिसमें से चार का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉ. गोदियाल

चर्चा में क्यों?

28 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉ. रविदत्त गोदियाल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जगमोहन राणा का कार्यकाल पूरा होने से पद खाली हो गया था। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कार्मिक विभाग ने आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉ. रविदत्त गोदियाल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है।

नोट :

- डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं और उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर ज़िम्मेदारी दी गई थी। हालाँकि, उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अब फिलहाल अध्यक्ष के तौर पर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है।
- गौरतलब है कि रिटायर्ड आईएएस राकेश कुमार ने 11 जून, 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी।

नोट :

मछली पालन को बढ़ावा देने को शुरू होगी 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना'

चर्चा में क्यों ?

30 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना'को शुरू करने की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि केंद्र सरकार की ओर से 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'संचालित है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के हिसाब से मत्स्य पालकों को कोई प्रोत्साहन सुविधा नहीं है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना'शुरू करने को मंज़ूरी दी है।
- इस योजना में मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिये तालाब, रेसवेज और अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये ऋण पर ब्याज दर में पाँच प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर में छूट दी जाएगी, जबकि दो प्रतिशत केंद्रीय योजना से मिलेगी।
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि पाँच साल होगी। इसमें चार हज़ार लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना में महिला समूहों को मछली पालन से जोड़ा जाएगा। साथ ही महिला समूहों को मछली पालन के लिये 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
- किसानों की तर्ज़ पर अब मत्स्य पालकों को भी बीमा की सुविधा मिलेगी। मत्स्य पालकों को एक लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। इसमें 90 प्रतिशत प्रीमियम प्रदेश सरकार देगी। प्रदेश में ही ट्राउट फिश का सीड तैयार किया जाएगा।

उत्तराखंड के सूरज पंवार ने रेस वॉकिंग में जीता गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों ?

30 अक्तूबर, 2023 को गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के सूरज पंवार ने 20 किलोमीटर की रेस वॉकिंग में प्रदेश के लिये एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीता।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सूरज पंवार ने 20 किलोमीटर की रेस एक घंटा 27 मिनट में पूरी की और गोल्ड मेडल जीता। इसे मिलाकर उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में अब तक दो स्वर्ण और एक रजत सहित आठ पदक जीत चुका है।
- उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. डीके सिंह के मुताबिक उत्तराखंड को अब तक दो स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। इससे पहले रुद्रपुर के निखिल भारती पेंचक सिलाट खेल के फाइनल में महाराष्ट्र के खिलाड़ी को 41-29 से हराकर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।
- वहीं उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने राष्ट्रीय खेलों की 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने यह दौड़ चार मिनट 16 सेकेंड में पूरी की। अंकिता मूलरूप से पौड़ी के जहरीखाल ब्लॉक के मेरुड़ा गाँव की रहने वाली हैं।
- विदित हो कि सूरज पंवार ने इससे पहले 2018 में अर्जेंटिना में आयोजित यूथ ओलंपिक की 5000 मीटर वॉकिंग रेस में रजत पदक जीता था। वर्ष 2018 में ही उन्होंने थाइलैंड में आयोजित एशियन चैंपियनशिप की 5000 मीटर रेस वॉकिंग में रजत जीता, जबकि पिछले साल दोहा में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में 24वाँ स्थान प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने किया सतर्कता सप्ताह का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

30 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत 'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किये जाने की घोषणा भी की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिये सर्विलांस व तकनीकि विशेषज्ञों की टीम का गठन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिये विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाए जाएँ।
- मुख्यमंत्री ने विजिलेंस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की माह में दो बार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिये सभी विभागीय सचिवों द्वारा अपने विभागों की नियमित मॉनीटरिंग की जाए।

नोट :

- उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिये जारी किये गए नंबर 1064 का भी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी शिकायत पर शीघ्र रिस्पॉन्स दिया जाए, शिकायत सही पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

30 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 में से 27 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इनमें 12 हज़ार वन पंचायतों में 1600 प्रकार की जड़ी-बूटियों को आजीविका से जोड़ने की योजना भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश की आबोहवा को महफूज रखने के लिये राज्य मंत्रिमंडल ने सोलर हीटर को बढ़ावा देने और ज़हरीला धुआँ उगलते कबाड़ वाहनों को सड़कों से हटाने की योजना को मंज़ूरी दी है।
- कबाड़ वाहन बेचेंगे तो नया वाहन खरीदने पर मिलेगी छूट
  - प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचने पर वाहन कर में छूट मिलेगी। व्यावसायिक वाहनों के लिये नया वाहन खरीदने पर यह छूट 15 प्रतिशत और निजी वाहन के लिये 25 प्रतिशत की होगी।
  - मंत्रिमंडल ने कबाड़ नीति को मंज़ूरी दी है। नीति को लागू करने पर केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपए की विशेष सहायता भी देगी।
- घरों में सोलर हीटर लगाने पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान
  - कैबिनेट ने सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना को मंज़ूरी दी है, जिसमें घरेलू उपभोक्ता अपने घरों में सोलर हीटर लगाएंगे तो सरकार इसके लिये 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी। वहीं व्यावसायिक उपयोग पर 30 फीसदी अनुदान मिलेगा। साथ ही बिजली बिल में प्रति लीटर 150 रुपए की छूट मिलेगी।
  - विदित हो कि 2014 में यह योजना बंद हो गई थी।
- 6000 से अधिक कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन में शामिल होने का मौका
  - नई पेंशन योजना में सेवारत् उन करीब 6000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति व अधिसूचना एक अक्तूबर 2005 से पहले जारी हो गई थी।
  - प्रदेश कैबिनेट ने केंद्र सरकार के मार्च 2023 में दिये गए विकल्प को अपनाया है।
- पहाड़ में बनेंगे हज़ारों चेक डैम, अथॉरिटी को मंज़ूरी
  - प्रदेश के 11 पर्वतीय ज़िलों में बारिश के पानी के उपयोग के लिये हज़ारों की संख्या में चेक डैम बनाए जाएंगे। इससे निचले मैदानी क्षेत्रों में बारिश के पानी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।

नोट :

- इसके लिये कैबिनेट ने जलागम निदेशालय के तहत स्पिंग एवं रिवर रेजुवेनेशन अथॉरिटी (सारा) को मंज़ूरी दी है।

- 35 हज़ार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ा
  - सचिवालय को छोड़कर प्रदेश के विभागों में तैनात करीब 35 हज़ार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष 2400 रुपए वर्दी भत्ता मिलेगा। अभी तक दो साल में पैंट, कमीज व अन्य अलग-अलग मदों में 4000 रुपए वर्दी भत्ता मिल रहा था। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
  - साथ ही चालक से लिपिक बनने के लिये होने वाली टाइपिंग परीक्षा में 4000 शब्दों के स्थान पर 2400 शब्द का मानक बनाया गया है।
- आठवीं पास आईटीआई करेगा तो हाईस्कूल में देनी होगी केवल हिन्दी की परीक्षा
  - प्रदेश में आठवीं पास जो छात्र आईटीआई का दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे, उन्हें हाईस्कूल की पूरी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। दसवीं पास करने के लिये उन्हें केवल हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
  - इसी तरह 10वीं के छात्र आईटीआई करने के बाद सिर्फ हिन्दी की परीक्षा पास कर 12वीं कर सकेंगे।
- वन पंचायतों में 628 करोड़ की जड़ी-बूटी पैदावर योजना को मंज़ूरी
  - कैबिनेट ने राज्य की 12 हज़ार वन पंचायतों में जड़ी-बूटी की पैदावार को बढ़ावा देने के लिये दो चरणों में 628 करोड़ रुपए की योजना को मंज़ूरी दे दी है।
  - यह योजना 10 वर्ष के लिये दो चरणों में 5000 हेक्टेयर में लागू होगी। इसके तहत स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा।
- कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
  - पर्यटन नीति में आसान होगी निवेश की प्रक्रिया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू
  - उद्योगों के विस्तार के लिये नीति में संशोधन को मंज़ूरी
  - नए गो सदन बनाने व पशु संरक्षण के लिये ज़िलाधिकारी को दिये अधिकार
  - आईएएस, आईआरएस व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी बन सकेंगे अपर कर आयुक्त
  - पावर हाउस के अपग्रेडेशन के लिये एडीबी के प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी गई।
  - कार्बेट की तर्ज़ पर राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन को मंज़ूरी
  - मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तीन प्रतिशत की सब्सिडी देगी सरकार
  - मॉडल जेल मैनुअल के आधार पर बनेगी कारागार नियमावली

नोट :